

VIKSIT GUJARAT INDUSTRIAL POLICY 2026

विकसित गुजरात औद्योगिक नीति 2026



Date of Announcement: June 15, 2026 | **घोषणा की तिथि:** 15 जून, 2026 | **Launched By:** Government of Gujarat (CM Bhupendra Patel)

Data collected by: **ManjeetsMathMagic**

1. VISION & EXECUTIVE SUMMARY / विजन और कार्यकारी सारांश

The Government of Gujarat officially launched the **Viksit Gujarat Industrial Policy 2026** on June 15, 2026, at Mahatma Mandir, Gandhinagar. Designed to align with the national blueprint of "Viksit Bharat 2047", this forward-looking policy targets an ambitious **₹10 Lakh Crore investment** over its operative term.

The core vision is to transition Gujarat into a global hub for advanced manufacturing, high-tech innovation, and sustainable ecological growth, accelerating the state's progression towards a **\$3.5 Trillion economy by 2047**.

गुजरात सरकार ने 15 जून, 2026 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में आधिकारिक तौर पर **विकसित गुजरात औद्योगिक नीति 2026** का शुभारंभ किया। "विकसित भारत 2047" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई यह नीति अपनी परिचालन अवधि में **₹10 लाख करोड़ के निवेश** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखती है।

मुख्य विजन गुजरात को उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing), हाई-टेक नवाचार और सतत पारिस्थितिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना है, जिससे **2047 तक \$3.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था** बनने की ओर राज्य की गति तेज हो सके।

₹10 Lakh Cr

Investment Target / निवेश का लक्ष्य

16 Sectors

Thrust Areas / मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र

\$3.5 Trillion

2047 Economy Goal / 2047 आर्थिक लक्ष्य

2. INTRODUCTION OF 'ULTRA MEGA' CATEGORY / 'अल्ट्रा मेगा' श्रेणी की शुरुआत

To incentivize large-scale global investments, the 2026 policy introduces a brand-new classification known as **Ultra Mega Industrial Units**. To qualify for this premium tier, projects must meet rigorous capital and employment criteria within the designated thrust sectors:

- **Minimum Investment:** ₹10,000 Crore.
- **Minimum Direct Employment:** 3,000 people.

बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए, 2026 की नीति में एक नई श्रेणी '**अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाइयाँ**' शुरू की गई है। इस विशेष श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को निम्नलिखित कड़े निवेश और रोजगार मानदंडों को पूरा करना होगा:

- **न्यूनतम निवेश:** ₹10,000 करोड़।
- **न्यूनतम प्रत्यक्ष रोजगार:** 3,000 लोग।

- **Incremental Scale:** For every additional ₹5,000 crore investment, an additional 500 jobs must be generated.

- **अतिरिक्त पैमाना:** प्रत्येक अतिरिक्त ₹5,000 करोड़ के निवेश पर 500 अतिरिक्त रोजगार सृजित करना अनिवार्य होगा।

Fiscal Incentive Cap: Eligible Ultra Mega units can claim fiscal support up to **40% of their Capital Investment**, with absolute flexibility to choose custom combinations of Capital Subsidies, Interest Subsidies, and Power Tariff Support.

राजकोषीय प्रोत्साहन सीमा: पात्र अल्ट्रा मेगा इकाइयाँ अपने पूंजी निवेश का **40% तक** वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। इसमें पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क सहायता का लचीला संयोजन चुनने का विकल्प उपलब्ध है।

3. EXPANDED THRUST SECTORS (16 AREAS) / विस्तारित थ्रस्ट सेक्टर्स (16 क्षेत्र)

The policy expands priority 'Thrust Sectors' from 9 to 16, embedding future-ready and deep-tech fields to secure early leadership positions in global supply chains:

ग्लोबल सप्लाय चेन में शुरुआती बढ़त हासिल करने के लिए नीति ने प्राथमिकता वाले 'थ्रस्ट सेक्टर्स' को 9 से बढ़ाकर 16 कर दिया है, जिसमें भविष्य की तकनीकों को शामिल किया गया है:

Core & Newly Added Thrust Sectors (English)	प्रमुख एवं नए जुड़े थ्रस्ट सेक्टर्स (Hindi)
• Semiconductor Ancillary & Design Units	• सेमीकंडक्टर सहायक और डिजाइन इकाइयाँ
• Drone Manufacturing & Robotics	• ड्रोन विनिर्माण और रोबोटिक्स
• Nuclear Power Equipment Manufacturing	• परमाणु ऊर्जा उपकरण विनिर्माण
• Textile Waste & E-Waste Recycling Industries	• कपड़ा अपशिष्ट और ई-कचरा पुनर्चक्रण उद्योग
• Green Hydrogen & Renewable Energy Ecosystem	• ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र
• Aerospace, Defense & Mobility (EVs)	• एयरोस्पेस, रक्षा और गतिशीलता (ईवी)
• Critical Mineral Processing & Capital Equipment	• महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण और पूंजीगत उपकरण
• Agro-Food Processing, Chemicals, & Healthcare	• कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और स्वास्थ्य सेवा

4. PROJECT THRIVE & REGIONAL BALANCE / प्रोजेक्ट थ्राइव और संतुलित क्षेत्रीय विकास

A flagship master-stroke in this policy is **Project THRIVE** (Transition for Harmonized Relocation and Inclusive Vibrant Economy). This mechanism incentivizes and facilitates the structured relocation of heavy and polluting industries away from congested municipal limits into dedicated outside zones.

Furthermore, to boost development in under-industrialized rural regions, the policy awards **additional tiered support** (higher interest and capital subsidies) for factories setting up operations outside major urban Tier-1 conglomerations.

इस नीति का एक मुख्य आकर्षण **प्रोजेक्ट थ्राइव (Project THRIVE)** है। इसका उद्देश्य भारी और भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नगर निगम की घनी सीमाओं से बाहर समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित (relocate) करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और त्वरित मंजूरी प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, कम औद्योगिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए, नीति प्रमुख शहरी टीयर-1 समूहों से बाहर स्थापित होने वाले कारखानों को **अतिरिक्त श्रेणीबद्ध सहायता** (उच्च ब्याज और पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करती है।

5. STARTUP ECOSYSTEM & GLOBAL ALLIANCES / स्टार्टअप इकोसिस्टम और वैश्विक गठबंधन

The policy introduces strict multi-layer technical screening involving groups like GVFL and iCreate to focus capital deployment onto high-potential tech startups. Key incentives include:

- **Global Co-Creation:** Up to **₹1 Crore assistance** for prototyping, marketing, and piloting products co-developed by a Gujarat startup jointly with an international startup (e.g., India-Israel Innovation bridge).
- **Lifecycle Tracking:** A fully data-driven software backend to track growth health and deploy intervention tools before units turn sick.

नीति में उच्च क्षमता वाले तकनीकी स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए GVFL और iCreate जैसी संस्थाओं को शामिल करते हुए बहुस्तरीय तकनीकी जांच शुरू की गई है। प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- **वैश्विक सह-निर्माण:** गुजरात के किसी स्टार्टअप द्वारा किसी विदेशी स्टार्टअप के साथ संयुक्त रूप से विकसित किए गए उत्पादों के प्रोटोटाइप, मार्केटिंग और पायलट रन के लिए **₹1 करोड़ तक की सहायता**।
- **लाइफसाइकिल ट्रैकिंग:** स्टार्टअप के विकास पर नज़र रखने और उनके बीमार होने से पहले आवश्यक सहायता देने के लिए डेटा-संचालित ट्रैकिंग सिस्टम।

6. FRAMEWORK FOR MSMES AND LARGE SCALE UNITS / एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए रूपरेखा

Continuing the legacy of foundational ease-of-doing business, the standard fiscal matrix provides competitive advantages across scale levels:

व्यापार करने की सुगमता को जारी रखते हुए, सामान्य वित्तीय संरचना सभी स्तरों के उद्योगों को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती है:

Category / श्रेणी	Capital Subsidy / पूंजीगत सस्सिडी	Interest Subsidy / ब्याज सस्सिडी	Special Incentives / विशेष प्रोत्साहन
Micro & Small / सूक्ष्म एवं लघु	25% to 30% depending on location	7% on loans up to ₹50 Lakh	₹2500/month employment grant for workers
Medium Enterprises / मध्यम उद्योग	Up to 20% with localized caps	5% to 7% on term loans	Assistance for green building & waste systems
Large & Thrust / बड़े और थ्रस्ट उद्योग	Tailored under Aatmanirbhar Scheme	7% subsidy up to 10 years based on Taluka category	Up to 40% absolute support for premium Ultra Mega units

Reference Notice: Compiled from official deployment declarations released by the Industries and Mines Department, Government of Gujarat on June 15, 2026. For single-window registrations, visit the Investor Facilitation Portal (IFP).

संदर्भ सूचना: उद्योग एवं खान विभाग, गुजरात सरकार द्वारा 15 जून, 2026 को जारी आधिकारिक घोषणाओं से संकलित।